कार्यान्वित करने की व्यवस्था है । सामुदायिक सिंचाई योजनाओं के सम्बन्ध में लघु तथा सीमान्त किसानों के लिए निर्धारित की जाने वाली लागत पर आधारित 50 प्रतिशत उपदान की अनुमति दी जाती है। शेष धनराशि को क्षेत्र में वित्तदायी संस्थाओं से लिए गए ऋण द्वारा पूरा किए जाने की आशा की जाती है। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, कमाण्ड क्षेत्र विकास आदि के विशेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत छोटे तथा सीमान्त किसानों के लिए इस प्रकार की सहायता भी उपलब्ध होगी। हाल ही में, यह निर्णय लिया गया है कि उपदान का लाभ ऐसे क्षेत्रों के लघु तथा सीमान्त किसानों को भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिन्हें लघु कृषक विकास एजेंसी, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, कमाण्ड क्षेत्र विकास आदि जैसे विशेष कार्यक्रमों में से किसी के अन्तर्गत भी नहीं लाया गया है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे ऐसी लघु सिंचाई योजनाओं, जिन्हें राज्य-भू-जल निदेशालय की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात क्षेत्र आधार पर शुरू किया गया है, के मुकाबले में लघु सिंचाई निर्माण-कार्यों पर उपदान देने हेतु निधियों की आवश्यकता का मूल्यांकन करें। इस प्रयोजन के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं।

केन्द्रीय सरकार कार्यालयों के लिए किराए की इमारतें

2095. **श्री सुखेन्द्र सिंह :**

डा० बसन्त कुमार पंडित :

श्री एस० जी० मुरुगय्यन :

क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 जून 1978 के दैनिक "नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित हुआ यह समाचार सच है कि राजधानी में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए किराये के रूप में 6 करोड़ रुपये की राशि की अदायगी करनी पड़ती है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार कार्यालयों के लिए इमारतों के निर्माण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इन इमारतों का निर्माण कब तक कर लिया जाएगा ; और

(ग) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार कार्यालयों के लिए कितना वार्षिक किराया अदा करना पड़ता है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं। राजधानी में कार्यालय-वास के लिए निर्माण और आवास मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा 2.21 करोड़ रुपये की राशि वार्षिक किराये क्षतिपूर्ति के रूप में अदा की जा रही है।

(ख) दिल्ली में पहले ही कई भवन निर्माणाधीन हैं और कुछ और भवनों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :—

(1) दिल्ली में मंजूर हो चुके और निर्माणाधीन कार्यालय भवन :—

भवन का नाम	फर्शी क्षेत्र (वर्ग मीटरों में)
बदरपुर-महरौली रोड पर भवन	19.970
साउथ ब्लाक, नई दिल्ली (ब्लाक बी और सी) के दक्षिण में प्लाट नं० 35 पर भवन	18,238
सैक्टर-11, रामकृष्णपुरम में बहुमंजिला भवन	28,606
सिविल लाइन्स में प्रकाशन विभाग के लिए प्रशासन भवन	2,742

उपर्युक्त भवनों के 1979 के अंत तक पूरा होने की संभावना है।

(2) ऐसे कार्यालय भवन जो मंजूर हो चुके हैं परंतु जिनके निर्माण का काम अभी शुरू नहीं किया गया है :—

	लगभग कुर्सी क्षेत्र (वर्ग मीटरों में)
लोधी रोड क्षेत्र में कार्यालय भवन-चरण-1	60,714

इस भवन का निर्माण कार्य दिसम्बर 1978 तक शुरू होने की उम्मीद है और इसे पूरा होने में 3 वर्ष लगेंगे।

एक और कार्यालय भवन बनाने का भी प्रस्ताव है जिसका कुर्सी क्षेत्र लगभग 65,000 वर्ग मीटर हो।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

Wild Buffaloes sanctuary in Maharashtra

2096. SHRI RAJE VISHVESHVAR RAO: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether wild Buffaloes, the species which are the largest found

in the world, live in the Indrawati river belt between Bhamnagarh of Maharashtra and Bastar District of Madhya Pradesh;

(b) is it a fact that the Maharashtra Government has decided to save that specie by starting a big sanctuary for them in Bhamnagarh area;

(c) is it a fact that that species is getting extinct and only about 60 to 70 in number are left; and

(d) if so, how far has the work progressed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH): (a) The Forests of Bhamnagarh in Chandrapur district constitute Indravati Basin in Maharashtra and survey of the tract in Maharashtra reveals complete absence of Wild Buffaloes. Wild Buffaloes, however, exist around Indravati river in Madhya Pradesh.

(b) The proposal for establishing a Wild Buffalo Sanctuary in Bhamnagarh was examined by the Govt. of Maharashtra in September, 1977 but the proposal was dropped because of total absence of Wild Buffaloes in the State.

(c) About sixty to seventy Wild Buffaloes occur in Madhya Pradesh only.

(d) To save this species from extinction the Govt. of India have in 1977-78 approved a Scheme to establish and assist the Kutru Sanctuary in the Bastar district of Madhya Pradesh with an outlay of Rs. 3,44,000/- (Rupees three lakhs and forty thousand only). Of the approved outlay, the Government of India have already released an amount of Rs. 1,00,000 during 1977-78.

10+2 patern of education in States

2097. SHRI DURGA CHAND:
SHRI R. MOHANARANGAM:
SHRI SURENDRA BIKRAM:

Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) the names of States which have switched over to 10+2 pattern of education;

(b) the names of States which have not introduced 10+2 system and the reasons given by each of them;

(c) whether the Central Government are considering to sanction special funds to those States which have introduced 10+2 for purposes of imparting training to teachers under the new system;

(d) if so, what is the amount given to each State so far and proposed to be given during the current financial year; and

(e) what is the assessment of Government in regard to popularity of the system in the country?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) and (b). The latest position regarding adoption of 10+2 structure of education by the States/Union Territories is as under:—

States/Union Territories which are having the 10+2 structure of school education are:—

1. Andhra Pradesh	2. Assam
3. Bihar	4. Gujarat
5. Jammu & Kashmir	6. Karnataka
7. Kerala	8. Maharashtra
9. Manipur	10. Meghalaya**

**There states/UTS have 10 years school followed by two years Pre-University.